able here. Out of the 174. we are using entirely on the basis of INSAT.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Matto.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, the question is about the underutilisa-lion of the INSAT-IB. The other day, Sir, when we were discussing the working ol the Ministry of Communications, I raised a very important point that in a sensitive State like Jammu and Kashmir we have only 24 STD lines from Srinagar t_0 Delhi and *vice versa* and it is next to impossible to get any STD link, any direct link, between Delhi and Srinagar although it is easier to P^{el} with $Londo_n$ or New York. are never be able to connect Srinagar with with Demi by STD and the honourable Minister said that he would look into it. Will the hon. Minister see $_{to}$ it that 1NSAT-1B i^ utilised for the purpose of augmenting the telecommunication lines between Srinagar and Delhi and vice versa?

SHRl SHIVRAJ PATIL; The question of underutilisation of INSAT-1B is coming up again and again and is being discussed in season and out of season. It is necessary ito understand that the INSAT facility is most sophisticated. If it has to be used for communication purposes, TV purposes, educational purposes and other purposes, the other facilities should be equally sophisticated. If these facilities are no* equally sophisticated, then it becomes very difficult to marry these two facilities and utilise them. So I would very respectfully like to submit to the House that in the circumstances available here and with the support we have for this kind of system what is being don_e by the Department and by the scientists is really very very laudable. As far as the specific question put by the hon. mernber is concerned, I 'shall have to get it examined and only then I can answer.

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Chairman, Sir, the Minister stated that INSAT-IB will be fully utilised by the end of the current calendar year. Sir, normally the problem of utilisation arises due to two facts: bottlenecks in the hardware development and also what can be called as communication gap as a result of the lack in 'he deve lopment of software. I would like to know from the Minister a's to what are the attempts made by the Ministry to meet the communication gap and what attempts have been made to have the software system developed. To the hest of my under* standing, the software system has been mostly developed in the Space Research Centre at Ahmedabad, Are there any plans to multiply such centre* so that the software which is so badly needed, and which, is needed for the communication gap is really there by the time the calendar year comes to an end and the INSAT-1B will be fully utilized?

SHRI SHIVRAJ PATIL. Sir, i_t is true that we may need a lot of software for utilizing not only this satellite but also the satellites which we woulj be launching afterwards. At present, we are utilizing the laboratory at Ahmedabad and we want to increase its capacity to produce software. Ihe question of multiplying laboratories is not on thi- anvil at present.

देश में विभिन्न राज्यों में धुआं-रहित चूल्हों का लगाया जाना

*246. श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री 2 मई, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 233 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कितने-कितने चूल्हे अब तक लगाये जा चुके हैं/बनाये जा चुके हैं और 1985-86 के वर्ष में 6 लाख चूल्हों में से प्रत्येक राज्य में कितने-कितने चूल्हे लगाये जायेंगे ; और

(ख) इस कार्य हेतु उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण की सुविधायें कहां-कहां उपलब्ध हैं और उस राज्य में उनके लिये कार्यान्वयन एजेन्सियां क्या-क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य और महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रखे गए विवरण "I" और "II" में दी गई है ।

(ख) उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास विभाग और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विकास एजेन्सी द्वारा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं 19 स्थानों पर हैं जैसे कि सभा के पटल पर रखे गए विवरण III में दिया गया है ।

विवरण–I

(दिसम्बर, 1983 से मार्च, 1985 तक)
स्थापित/निर्मित उन्नत चूल्हों की संख्या

आन्ध्र प्रदेश	99,967
बिहार	2,228
गुजरात	30,882
हरियाणा	88,583
हिमाचल प्रदेश	32,811
जम्मू और काश्मीर	4,393
केरल	13,160
कर्नाटक	49,324
मध्य प्रदेश	1,060
महाराष्ट्र	80,785
उड़ीसा	35,463
पांडिचेरी	3,233
पंजाब	44,783
राजस्थान	1,35,505
तमिलनाडू	81,461
उत्तर प्रदेश	77,136
पश्चिम बंगाल	16,630
चंडीगढ़	3,498
दादर नगर हवेली	529
दिल्ली	9,309
गोवा, दमन और दीव	2,062
त्रिपुरा	107
योग :	6,12,909

विवरण–II

1985–86 के लिये प्रस्तावित निर्मित/स्थापित किये जाने वाले उन्नत चूल्हों का 1985–86 का लक्ष्य

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लक्ष्य
आंध्र प्रदेश	45,000
असम	5,000
बिहार	20,000
गुजरात	30,000
हरियाणा	45,000
हिमाचल प्रदेश	25,000
जम्मू और काश्मीर	15,000
कर्नाटक	20,000
केरल	20,000
मध्य प्रदेश	20,000
महाराष्ट्र	35,000
मणीपुर	2,000
मेघालय	2,000
मिजोरम	1,000
नागालैंड	2,000
उड़ीसा	25,000
पांडिचेरी	3,000
पंजाब	35,000
राजस्थान	40,000
सिक्किम	1,000
तमिलनाडू	30,000
त्रिपुरा	1,000
उत्तर प्रदेश	45,000

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लक्ष्य
पश्चिमी बंगाल	20,000
अंडमान और निकोबार	1,000
अरुणाचल प्रदेश	1,000
चंडीगढ़	2,000
दादर, नगर हवेली	1.000
दिल्ली	5,000
गोवा, दमन और दीव	2,000
लक्ष्यद्वीप	1.000
योग :	5,00,000
आवश्यकतानुसार दूसरी एजेंसियों को आबंटित करने के लिए आरक्षित रखे गए लक्ष्य	1.00,000
कुल योग :	6,00,000

विवरण–III

उत्तर प्रदेश में उन्नत चूल्हे की प्रशिक्षण सुविधाएं

आगरा
इलाहाबाद
बरेली
बिजनौर
फैजाबाद
गाजियाबाद
गोरखपुर
जलांन
जसपुर (नैनीताल)
झांसी
लखनऊ
मेरठ
नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)
नैनीताल
पौड़ी गढ़वाल
रायबरेली
सहारनपुर
सुलतानपुर
वाराणसी

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट "ए" में जाहिर है कि असम में एक भी नहीं, बिहार, जिसकी बहुत बड़ी आबादी है वहां केवल 2228, मध्य प्रदेश, उसकी भी बहुत बड़ी आबादी है वहां पर 1060, जब कि पांडिचेरी और चंडीगढ़, जिन की आबादी कम है वहां तीन और सवा तीन हजार चूल्हों का निर्माण हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और असम की सरकारों ने इसमें कोई दिलचस्पी ली है या किस कारण से वहां ये चूल्हें नहीं लगाये जा सके हैं?

दूसरा भाग मेरे प्रश्न का यह है कि जहां-जहां चूल्हे लगाए गए हैं वहां सरकार क्या कोई अनुदान देती है? यदि हां, तो किन लोगों को यह अनुदान दिया जाता है?

श्री शिवराज पाटिल : श्रीमन्, यह जो काम है, सैटेलाइट का जितना काम है उस से भी ज्यादा ऐहतियात से लोगों की मदद से करने का काम है। जब तक कि प्रान्त के स्तर पर, जिला और तालुका स्तर पर और गांव के स्तर पर लोगों की मदद उपलब्ध नहीं होती है, उस वक्त तक इस काम को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर घर में एक चूल्हा हमें ले जाना है। यहां जो आंकड़े हमने दिये हैं, उनसे पता चलता है कि किस प्रान्त में अच्छा काम हुआ है, किस प्रान्त में अच्छी मशीनरी अवैलेबल है। यह जाहिर है कि जहां पर नहीं हुआ है, वहां पर ज्यादा होने की जरूरत है, वहां इसके लिए कोशिश की जाएगी।

दूसरा सवाल यह है कि हम कुछ अनुदान या सबसिडी देते हैं या नहीं। हम सौ प्रतिशत सबसिडी देते हैं शैडूल्ड कास्ट और शैडूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को। और को 50 से 75 प्रतिशत तक देते हैं। शैडूल्ड कास्ट को हर चूल्हे के लिए 5 रुपये दे देते हैं और ट्रैनिंग के लिए भी उसकी व्यवस्था की गई है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : श्रीमन्, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ट्रेनिंग की जो व्यवस्था आपने की है, इसके कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है ? ट्रेनिंग में कोई इमाल्यूमेंटस भी मिलते हैं ? एकाध दिन की ट्रेनिंग है या कितने दिनों की है ? क्या रोजाना वे आते रहते हैं और जाते रहते हैं? इसके अतिरिक्त यदि एम० पी० लोग इसमें रुचि रखने वाले हों तो जो आपने चूल्हे बनाये हैं, जिन से हमारी माताओं व बहनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सकती है, तो क्या ऐसे चूल्हे की रुचि रखने वाले एम० पी० लोगों को दिखाने की दिल्ली में व्यवस्था करेंगे ?

श्री शिवराज पाटिल : श्रीमन्, जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, 10 के करीब हम ग्रुप में लोगों को बुलाते हैं और उन पर 10 हजार रुपये तक खर्च करते हैं खाने-पीने और उन लोगों के आने-जाने में। इसके लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों में ही ट्रेनिंग दी जाती है।

जहां तक चूल्हे बनाने या दिखाने का सवाल है, हमें खुशी होगी कि इस प्रकार के जो सौर ऊर्जा और दूसरे चूल्हे हमने बनाये हैं, हम एक प्रदर्शनी बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे और आप चाहेंगे तो आपके पास भेज भी देंगे और आप से पैसे जरूर ले लेंगे।

SHRl MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE. Mr. Chairman, the smokeless *chulha* has brought a revolution in villages. No more is tnere cooking with tears. And it is also with joy. Now. I find from the statement which has been placed by th.: honourable Minister that in some State- the target was, in fact. si\ lakhs but the number of actually installed i_s 8,12,909 which snows that the performance is really remarkable and deserves ail ihe compliments. In my State they had placed Ihe target at 35,000 but the actual installation is 2J times, *i.e.,* 80,000. Same is tbe case with $_a$ State like Gujarat. with Andhra Pradesh, where the target was 45,000 but the actual installation is 99.000. And then we have the usual chronic Stales like Bihar…

MR. CHAIRMAN: You put your question.

SHRl MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: 1 would like tc ask the honourable Minister what steps me being taken to popularise and increase the instnllation in these States which are lagging behind the targets.

SHRl SHIVRAJ PATlL: We would like to talk to the concerned departments and officers in the different States and we will urge them to take it up with right earnestness and whatever help can be giver. Irom the Centre will be given to them. In fact, it does not need any financial help o_r technical help as such. What is needed is the will to do *it.* And if that wilj i_s created, we will be able to reachi the target and we will be able to do much mor,; than what is expected.

SHRIMATI KANAK. MUKHERJEE: May I know whether there is any allocation $_0$f found fixe<j State-wise? Secondly, who are the people selected for the training? What are the qualifications needed for it? And is there any job guarantee after th_e training? Are the women given special preference in this? And whal is th© prospect of getting a job after this training?

SHRI SHIVRAJ PATlL: Sir, we spent Rs. 4 crores; then we spent Rs. 5 crores. And we are expecting to spend Rs. 6 crores on this. The Rural Development .Department and the Khadi and the Village Industries Boards are expected to help us in these matters. But there is no well-planned co-ordination between "the Departments available at the Centre. We go to the Staies. We talk to them. And we try to select that Department which can come into contact with the individuals and the people in the rural areas easily, and through them we reach this chulah to i he people.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : चेयरमैन साहब, यह क्योंकि क्रांतिकारी और प्रगतिशील कदम है...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह तो चूल्हा छोड़ चुकी हैं। इनको क्यों अवसर दे रहे हैं।

श्री सभापति : लेडीस फर्स्ट

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महिला कभी चूल्हा नहीं छोड़ती। मैंने भी कभी चल्हा नहीं छोड़ा और न छोड़ूंगी। क्योंकि यह एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी कदम है और अच्छी दिशा में जा रहा है और यह जानते हुए कि सफलता बहुत मात्रा में गैर सरकारी और महिलाओं की संस्थाओं पर निर्भर है तो क्या सरकार इन संस्थाओं के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन दे रही है जिस से वे इन चूल्हों की बात बता कर जन-जन और गांव-गांव में जाकर इस भावना को और इस चीज को ज्यादा तेजी से ले जा सकें?

श्री शिवराज पाटिल : श्रीमन्, असल में हमारी बात तो ऐसी है कि जो सब से अहम चीज है और आसानी से मिलती है उसकी शायद हमारे मन में बहुत कम इज्जत होती है। जैसे कि हवा और खाना सब से अहम है आसानी से घर में मिलता है इसलिए कभी भी उसकी कीमत हम नहीं लगाते। चूल्हा बहुत ही अहम चीज है जिसकी वजह से हमारी बहनों और माताओं को मदद होने वाली है। हमारा फ्यूल बचेगा, यह ध्यान में रखकर हम सरकारी संस्थाओं और उसके साथ-साथ गैर-सरकारी संस्थाओं से और व्यक्तियों के माध्यम से इसको हर आदमी और हर स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति जी, गैस चूल्हे वाले इस दर्द को नहीं जानेंगे। गांव में, झोंपड़ी में जो करोड़ों मां खाना बनाते समय धुएं से अपनी आंखों की रोशनी नष्ट कर रही हैं, अंधी हो जाती हैं समय से पहले तो क्या उस पीड़ा को जानते हुए सबसे अधिक पैसा उसमें देंगे और हर प्रखण्ड में कम से कम चूल्हा बनाने का केन्द्र स्थापित करेंगे जिस से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके? पंचायती स्तर पर, जिला स्तर पर इसका प्रचार करने का आपका कोई विचार है जिससे जल्दी से जल्दी ये महिलायें धुएं से रहित चूल्हे का अपने घरों में प्रयोग कर सकें?

श्री शिवराज पाटिल : महिलाओं की जो संस्थायें हैं उनकी खासकर इस काम के लिए हम मदद ले रहे हैं और उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, प्रोत्साहित करते रहेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : महिलाओं की संस्थायें केवल शहरों में हैं और शहरों में गैस है।

श्री शिवराज पाटिल : यह काम ऐसा है जिसको हम गांव, जिला और स्टेट के स्तर पर कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप इसको 20 सूत्री कार्यक्रम में क्यों नहीं जोड़ देते? मैं यह जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इसके लिए कितनी रकम रखी है, चूल्हे के प्रचार के लिए, अनुदान के लिए कितनी राशि रखी है तथा प्रशिक्षण के लिए कितनी?

श्री शिवराज पाटिल : रकम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी यह फाइनालाइज होना है। लेकिन आप यह ध्यान में रखिये कि जितना हमने खर्च किया है उससे ज्यादा रखेंगे।

श्री सत्यपाल मलिक : मान्यवर, इस मुल्क में सब से ज्यादा अन्याय गांव की औरतों के साथ खाना पकाने के मामले में होता है। इस मामले को इस देश में गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलाजी मिनिस्ट्री से ही संबंधित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के लिए... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Now, Papers to be laid on the Table of the House. Please sit down. Nothing Will be recorded. Now, Papers to be Laid on the Table of the House.